भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 1661
मंगलवार, 10 फरवरी, 2026/21 माघ,1947 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाइयां

1661. श्री गणेश सिंहः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का स्वास्थ्य सप्लिमेंट्स और डेयरी उप-उत्पादों के लिए कम लागत वाले प्रोटीन उत्पादों जैसे व्हे और प्रोबायोटिक कल्चर के थोक उत्पादन हेतु सहकारी क्षेत्र में संकुल-आधारित प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए किसी विशिष्ट योजना का विचार है;

(ख) क्या सरकार ए2 दूध और इसके उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग के मद्देनजर, महिला नेतृत्व वाली ग्राम स्तरीय सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध शीतलन केंद्रों, ए2 ब्रांडिंग और गुणवत्ता प्रमाणीकरण में सहयोग कर दूध की प्रत्यक्ष निर्यात आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए कोई पहल कर रही है;

(ग) क्या सरकार का इस सहकारी मॉडल को जिला-आधारित डेयरी और मूल्यवर्धन संकुल के रूप में विकसित करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार इस सहकारी मॉडल और जिला-आधारित डेयरी और मूल्यवर्धन संकुल विकसित करने की योजना पर विचार कर रही है;

(ङ) क्या मध्य प्रदेश के सतना और विंध्य क्षेत्र का प्रायोगिक जिलों के रूप में चयन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): स्वास्थ्य सप्लिमेंट्स और डेयरी उपोत्पादों जैसे व्हे और प्रोबायोटिक कल्चर के लिए कम लागत वाले प्रोटीन उत्पादों के थोक विनिर्माण हेतु सहकारी क्षेत्र में क्लस्टर आधारित प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने की कोई विशेष योजना का अभी विचार नहीं है । तथापि, सरकार ने निम्नलिखित के माध्यम से मूल्य वर्धित प्रसंस्करण में उल्लेखनीय निवेश किया है:

i) एनपीडीडी घटक ख: दिनांक 31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार 9 राज्यों में 42 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिससे 262 एमपीटीडी (मीट्रिक टन प्रति दिन) मूल्य-वर्धित प्रसंस्करण क्षमता का निर्माण हुआ है ।

ii) सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (एसपीसीडीएफ): इस नवस्थापित बहुराज्य समिति का लक्ष्य सुरक्षित और स्वच्छ डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांगों के समर्थन में कुशल प्रसंस्करण सुविधाओं में निवेश करना है ।

iii) एनसीडीसी सहायता: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) मूल्य-वर्धित डेयरी परियोजनाओं की अवसंरचना के निर्माण, आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) सरकार मौजूदा पहलों के माध्यम से डेयरी निर्यात इकोसिस्टम को सशक्त कर रही है । राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) सहकारी क्षेत्र से अधिशेष उपज के प्रत्यक्ष निर्यात की सुविधा के लिए एक अंब्रेला संगठन के रूप में कार्य करता है, ताकि प्राथमिक सहकारी समितियों की वैश्विक बाजार पहुंच सक्षम की जा सके । श्वेत क्रांति 2.0 और नंदिनी सहकार योजना के अधीन महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों को उनकी उद्यमशीलता क्षमता में वृद्धि के लिए रियायती वित्त, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से सहयता प्रदान की जाती है । इसके अलावा, शीत श्रृंखला केंद्रों और गुणवत्ता मानकों को सुद्दढ़ करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) और डेयरी विकास के लिए विशेष पैकेज (एसपीडीडी/एसपीसीडीएफ) के अंतर्गत दूध शीतालन केंद्रों जैसी अवसंरचना और गुणवत्ता सुधार उपायों को सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, वर्तमान में ए-2 दूध की ब्रांडिंग के लिए विशेष रूप से कोई अलग योजना अधिसूचित नहीं की गई है ।

(ग) और (घ) सरकार निम्नलिखित पहलों द्वारा विकेंद्रीकृत क्लस्टरों के मॉडल की ओर बढ़ रही है:

(i) मंत्रालय पैक्स को भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन सेवाएं प्रदान करने वाले बहु-सेवा केंद्रों में रूपांतरित कर रहा है ।

(ii) राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) निविष्टि लागत को कम करने और प्राथमिक उत्पादकों के लिए बाजार लिंकेज में सुधार करने के लिए क्लस्टर-आधारित जैविक खेती मॉडल को बढ़ावा देता है ।

(iii) सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को 20 राज्यों के 20,000 से अधिक गांवों को एक संगठित सहकारी संरचना के रूप में एकीकृत करने के लिए बनाया किया गया है जो पशुधन के पोषण और आधुनिक डेयरी प्रथाओं पर जोर देता है ।

(ङ) और (च) इस मंत्रालय द्वारा अभी तक मध्य प्रदेश के सतना और विंध्य क्षेत्र को पायलट जिलों के रूप में चयनित करने के किसी प्रस्ताव पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है ।

*****